RNI No#MPBIL/2013/49052

INVESTMENT AVENUES®
इन्वेस्टमेंट ऐवेन्यूस

भोपाल, शनिवार 01 से 7 जुलाई 2026 | भोपाल , मध्यप्रदेश से प्रकाशित | वर्ष- 14 | अंक-103 | पृष्ठ- 8 | मूल्य- रु. 5 /-

आरबीआई का बड़ा फैसला: रेपो रेट 5.25% पर यथावत, होम लोन ईएमआई में राहत

त्योहारी सीजन में हाउसिंग डिमांड को मिलेगा जोरदार बढ़ावा, खरीदारों में बढ़ेगा भरोसा

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी ताजा मौद्रिक नीति में रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला लिया है। इस निर्णय से होम लोन की ईएमआई स्थिर रहने की उम्मीद है, जिससे त्योहारी सीजन में आवास मांग को समर्थन मिलने की संभावना बढ़ गई है।

रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। इसे स्थिर रखने से बैंकों द्वारा होम लोन समेत अन्य ऋणों की ब्याज दरें जल्द बढ़ाने की संभावना कम हो गई है। इससे होमबॉयर्स को अपनी वित्तीय योजना बनाने में राहत मिलेगी।

रियल एस्टेट डेवलपर्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि स्थिर ईएमआई से दिवाली और शादी के मौसम में पूछताछ और बिक्री दोनों बढ़ सकती है। खासकर अफोर्डेबल और मिड-सेगमेंट हाउसिंग में मांग मजबूत रहने की उम्मीद है।

विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा माहौल में पहले होम खरीदने वाले और अपग्रेड करने वाले दोनों खरीदारों को भरोसा मिलेगा। कई डेवलपर्स ने नए प्रोजेक्ट लॉन्च और त्योहारी ऑफर तैयार कर रखे हैं।

आरबीआई का यह रुख वृद्धि को समर्थन देने और महंगाई पर नजर रखने के बीच संतुलन का संकेत देता है। स्थिर उधारी लागत से न केवल आवास क्षेत्र बल्कि समग्र खपत और निवेश को भी बल मिलने की उम्मीद है। खरीदारों के लिए यह अपेक्षाकृत निश्चितता का समय है।

ग्वालियर के नाम बड़ी उपलब्धि, देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित होगा!

डीओटी और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एमओयू, ₹12,000-15,000 करोड़ निवेश का लक्ष्य

भोपाल: दूरसंचार विभाग (डीओटी) और मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (TMZ) स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी की उपस्थिति में हुआ।

TMZ को 170 एकड़ भूमि पर प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार ने यह भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई है, जबकि केंद्र सरकार ने फेज-1 इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹493 करोड़ का अनुदान दिया है। यह जोन टेलीकॉम उपकरण निर्माण, अनुसंधान, परीक्षण और नवाचार का एकीकृत केंद्र बनेगा।

परियोजना से कुल ₹12,000 से 15,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद है। फेज-1 में लगभग ₹5,000 करोड़ के प्रारंभिक निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं। इससे करीब 14,000 प्रत्यक्ष कुशल रोजगार सृजित होने का अनुमान है।

यह पहल आत्मनिर्भर भारत के विजन को मजबूत करेगी और घरेलू टेलीकॉम विनिर्माण क्षमता बढ़ाएगी। विशेष प्रयोजन के माध्यम से परियोजना संचालित होगी, जिसमें राज्य की 51 प्रतिशत और केंद्र की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। ग्वालियर को मध्य भारत का प्रमुख टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है।

GRSE Wins ₹1,032 Crore ONGC Contract for Four Advanced Offshore Vessels

Order Strengthens Commercial Shipbuilding Portfolio and Supports Offshore Energy Operations

Kolkata: Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd (GRSE), a Navratna defence public sector undertaking, has secured a ₹1,032 crore contract from Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) for the design, construction and delivery of four Platform Supply Vessels (PSVs).

GRSE received the Notification of Award on July 30, 2026. The vessels will be built as per Indian Register of Shipping rules and feature advanced hybrid propulsion systems, including electrically driven azimuth thrusters and lithium-ion battery energy storage. Each vessel will measure about 80 metres in length, with a 20-metre beam, 3,000-tonne deadweight capacity, endurance of over 45 days and a clear deck area of around 650 square metres.

These vessels will support ONGC's offshore exploration and production activities by providing logistics and operational assistance at sea. The contract marks a significant addition to GRSE's commercial shipbuilding order book and reflects the company's diversification beyond traditional defence projects.

The substantial order is expected to enhance revenue visibility and strengthen GRSE's order book over the medium term. Analysts generally view such large, multi-year contracts positively for defence PSUs, as they improve capacity utilisation and provide earnings visibility. While short-term stock movements depend on broader market sentiment, the deal is seen as a constructive development for GRSE's long-term performance and its growing presence in the offshore support vessel segment.

टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एएसएमएल मिलकर भारत में चिप उपकरण कंपोनेंट बनाने की राह तलाश रहे

लिथोग्राफी मशीनों के लिए सब-असेंबली निर्माण पर प्रारंभिक चर्चा, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मिलेगा नया आयाम

नई दिल्ली: टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी एएसएमएल (ASML) भारत में उन्नत चिप-निर्माण उपकरणों के कंपोनेंट और सब-असेंबली बनाने की संभावना तलाश रही हैं। दोनों कंपनियों के बीच प्रारंभिक स्तर की चर्चा चल रही है, जो भारत को सेमीकंडक्टर लिथोग्राफी इकोसिस्टम में शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

एएसएमएल दुनिया की एकमात्र कंपनी है जो सबसे उन्नत एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट (ईयूवी) लिथोग्राफी मशीनें बनाती है। ये मशीनें अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन के लिए जरूरी हैं। सूत्रों के अनुसार, दोनों कंपनियां भारत में लोकलाइजेशन बढ़ाने और साझेदारी मजबूत करने पर विचार कर रही हैं।

अभी पूरा उपकरण भारत में बनाना संभव नहीं है, लेकिन कुछ हिस्सों जैसे प्रिसिजन मैकेनिकल पार्ट्स, फ्रेम, केबलिंग, कनेक्टर, पीसीबी और कम जटिल मेकाट्रॉनिक मॉड्यूल के निर्माण की संभावना तलाशी जा रही है। यह चर्चा 16 मई को हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुरूप है, जिसके तहत एएसएमएल टाटा के धोलेरा फैब के लिए लिथोग्राफी उपकरण उपलब्ध कराएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि एएसएमएल के लिए कंपोनेंट बनाने से भारतीय कंपनियां वैश्विक सप्लाई चेन में विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता बन सकती हैं। यह कदम भारत की सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षाओं को मजबूत करेगा और घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा।

Centre Plans Co-Investment with Venture Capitalists under ISM 2.0 to Unlock Larger Funding Pool

Move Aims to Strengthen Full Semiconductor Value Chain and Attract More Players

New Delhi: The government is planning to co-invest with venture capitalists under the second phase of the India Semiconductor Mission (ISM 2.0) to create a larger pool of funds and attract a wider range of companies across the semiconductor value chain.

According to MeitY Secretary S. Krishnan, ISM 2.0 will go beyond traditional grant-based support. The Centre intends to partner with established venture capital and deep-tech funds so that public capital can leverage private investment, making a substantially larger quantum of funds available for the ecosystem.

The focus of the new phase will cover the entire semiconductor value chain, including equipment, materials, gases, chemicals and related inputs required for a self-sustaining domestic industry. Officials believe this approach will help establish a more substantial and complete presence of semiconductor manufacturing and design capabilities in India.

The government proposes to work with funds selected on commercial principles, including those supported by SIDBI or other fund-of-funds structures. A whitelist of eligible funds will be prepared before the co-investment mechanism is rolled out.

This shift marks a significant evolution from the first phase of ISM, which primarily relied on incentives and grants. By sharing risk with private investors, the Centre aims to crowd in more capital, encourage innovation-led startups and accelerate the build-out of a robust semiconductor ecosystem aligned with India's long-term technology and self-reliance goals.

धार का पीएम मित्रा पार्क: तीसरे दौर की भूमि आवंटन प्रक्रिया शुरू!

2,158 एकड़ के भारत के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क में निवेश का सुनहरा मौका – 18 अगस्त तक आवेदन करें

उज्जैन: मध्य प्रदेश के धार जिले में विकसित हो रहे पीएम मित्रा (PM MITRA) पार्क में भूमि आवंटन का तीसरा दौर शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) ने 29 जुलाई 2026 से आवेदन प्रक्रिया शुरू की है, जो 18 अगस्त 2026 शाम 6 बजे तक चलेगी। यह भारत का सबसे बड़ा पीएम मित्रा पार्क है, जो लगभग 2,158 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है।

यह पार्क प्रधानमंत्री के 5एफ मॉडल – फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन – पर आधारित है। इसमें टेक्सटाइल वैल्यू चेन की पूरी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध कराई जा रही हैं। पार्क में विश्व स्तरीय कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रतिस्पर्धी यूटिलिटी टैरिफ, जेडएलडी आधारित सीईटीपी, आरएंडडी और ट्रेनिंग सुविधाएं, वेयरहाउसिंग तथा सामाजिक बुनियादी ढांचा शामिल है।

पहले दो चरणों में पहले ही 1,100 एकड़ से अधिक भूमि आवंटित की जा चुकी है। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। तीसरे चरण में शेष भूमि आवंटित की जाएगी, जिससे टेक्सटाइल और अपैरल मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को और अवसर मिलेंगे।

केंद्र और राज्य सरकार की आकर्षक प्रोत्साहन योजनाएं, कम लागत वाली उपयोगिताएं और प्लग-एंड-प्ले सुविधाएं इस पार्क को विशेष बनाती हैं। धार का स्थान इंदौर डिवीजन में होने से लॉजिस्टिक्स और बाजार पहुंच आसान है। यह पार्क भारत को वैश्विक टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इच्छुक निवेशक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अवसर टेक्सटाइल क्षेत्र में रोजगार सृजन, निर्यात बढ़ाने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगा।

पीएम मित्रा पार्क धार टेक्सटाइल उद्योग के लिए गेम-चेंजर साबित हो रहा है। तीसरे दौर की आवंटन प्रक्रिया में भाग लेकर निवेशक इस

बड़े अवसर का लाभ उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार और एमपीआईडीसी निवेशकों का स्वागत कर रहे हैं।

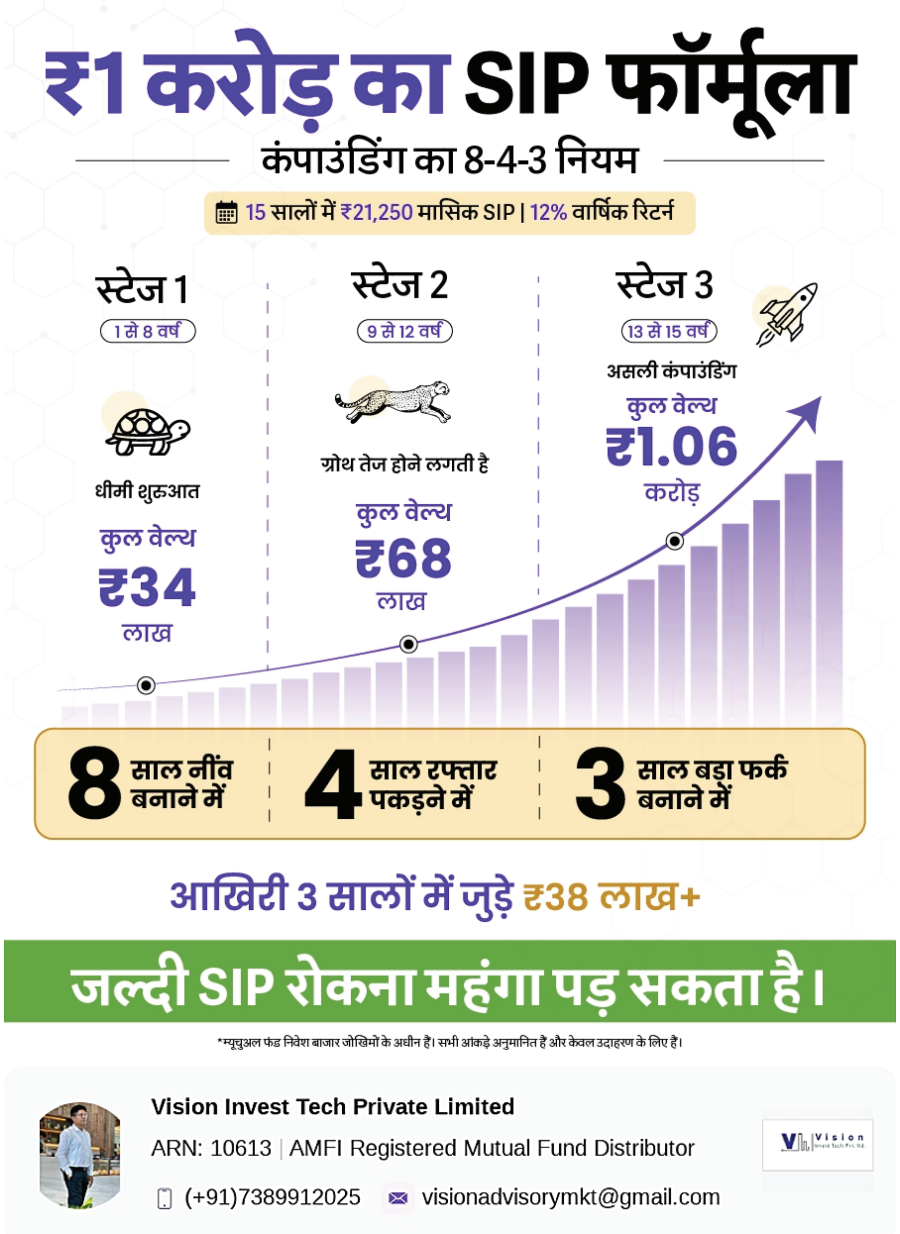

Ola Electric Powers into Utility Storage: Signs Landmark MoU with Axis Energy for 20 GWh BESS by 2032

First partnership for upcoming Mahashakti platform signals major diversification beyond EVs as India races toward massive energy storage needs

New Delhi: Ola Electric Mobility has formally entered the utility-scale Battery Energy Storage Systems (BESS) segment by signing a Memorandum of Understanding with renewable energy developer Axis Energy. The agreement outlines the potential deployment of up to 20 GWh of battery energy storage systems by 2032, marking the first large-scale commercial partnership for Ola's forthcoming Mahashakti platform.

Mahashakti, scheduled for launch on August 15, 2026, is designed as an India-designed and India-manufactured energy storage platform targeting commercial, industrial and utility-scale applications. Under the MoU, deployments are expected to scale up to 5 GWh annually from 2028 onwards.

Axis Energy is developing one of India's largest pipelines of storage-backed renewable projects. The company has secured grid approvals for more than 3,750 MW of projects in Andhra Pradesh and Rajasthan, along with an additional pipeline of around 3,500 MW. These projects, spanning firm and dispatchable renewable energy (FDRE), hybrid and other configurations, will require large-scale BESS to improve renewable integration, enhance grid reliability and deliver firm, round-the-clock clean power.

India's energy transition is expected to drive unprecedented demand for storage. The Central Electricity Authority estimates the country will need over 400 GWh of battery energy storage capacity by 2032. Ola positions Mahashakti as a vertically integrated cell-to-system solution aimed at delivering superior safety, performance and total cost of ownership across renewable energy integration, industrial power, grid infrastructure and data-centre applications.

Ola Electric Chairman and Managing Director Bhavish Aggarwal described Axis Energy as the company's first large-scale partner and an important early validation of Mahashakti's potential. He noted strong interest from other industry players and said the MoU strengthens momentum for long-term partnerships. The announcement triggered a sharp rise in Ola Electric's share price, reflecting investor optimism about the new growth avenue beyond electric two-wheelers.

For investors, the move highlights Ola's push to leverage its battery technology expertise into a high-growth adjacent market as India scales renewable capacity and seeks reliable clean power solutions.

टाटा पावर का बड़ा कदम: आंध्र प्रदेश में 5,750 करोड़ का हरित ऊर्जा प्रोजेक्ट शुरू!

800 मेगावाट सोलर-विंड हाइब्रिड परियोजना से 4,000 रोजगार और किसानों को लीज आय का लाभ

भोपाल: टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (टीपीआरईएल) ने आंध्र प्रदेश में 5,750 करोड़ रुपये के निवेश वाले 800 मेगावाट के स्वच्छ ऊर्जा प्रोजेक्ट का भूमि पूजन समारोह आयोजित कर काम शुरू कर दिया है। यह परियोजना कुरनूल जिले के पट्टिकोंडा में 400 मेगावाट सोलर और अनंतपुरम जिले के कानेकल्लू में 400 मेगावाट विंड पावर क्षमता को जोड़ती है।

प्रोजेक्ट के विंड हिस्से का विकास टीपीआरईएल कर रहा है, जबकि सुजलॉन इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) कार्य संभालेगा। सोलर क्षमता में से 200 मेगावाट एनटीपीसी के लिए फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी (एफडीआरई) प्रोजेक्ट के रूप में विकसित होगा, जिसमें 25 मेगावाट/50 मेगावाट-ऑवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शामिल है। शेष 200 मेगावाट सोलर क्षमता भविष्य के आवंटन के लिए उपलब्ध रहेगी।

यह परियोजना आंध्र प्रदेश की इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी के तहत लागू की जा रही है। इसमें अनंतपुरम-II और कुरनूल-4 सीटीयूआईएल सबस्टेशनों पर 800 मेगावाट इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम कनेक्टिविटी सुरक्षित की गई है, जिससे राष्ट्रीय ग्रिड के माध्यम से बिजली का कुशल निकासी संभव होगा। कुल 3,462 एकड़ भूमि का उपयोग होगा, जिसमें 2,700 एकड़ सोलर और 760 एकड़ विंड के लिए आरक्षित है।

इससे विकास, निर्माण और संचालन चरणों में लगभग 4,000 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही स्थानीय किसानों को वार्षिक लीज रेंटल आय मिलेगी, जिससे 1,100 से अधिक कृषक परिवार लगभग तीन दशक तक स्थिर आय प्राप्त कर सकेंगे। टाटा पावर के सीईओ व एमडी प्रवीर सिन्हा ने कहा कि यह परियोजना भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को तेज करने और राउंड-द-क्लॉक विश्वसनीय हरित बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

आंध्र प्रदेश सरकार के मंत्री नारा लोकेश ने भी इस मौके पर मौजूद रहकर राज्य को वैश्विक निवेशकों की पसंदीदा जगह बताते हुए

परियोजना का स्वागत किया। यह निवेश टाटा पावर के रिन्यूएबल पोर्टफोलियो को मजबूत करेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था तथा ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देगा। निवेशकों के लिए यह भारत के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में बड़े अवसरों का संकेत है।

Eicher Motors Locks in 4 Lakh Sq Ft at Casagrand Industrial Park Near Chennai

Seven-year lease in Sriperumbudur strengthens Royal Enfield's supply chain footprint as demand for Grade-A industrial space surges

Chennai: Eicher Motors, the parent of Royal Enfield motorcycles, has leased nearly 4 lakh square feet of industrial space at Casagrand Industrial Park in Sriperumbudur on the outskirts of Chennai. The seven-year lease covers 3.92 lakh sq ft (chargeable area 392,251 sq ft) in the Santhavelur locality and underscores the company's continued expansion in one of India's key automotive manufacturing hubs.

The agreement is with landlord Casagrand Blue Horizon Private Limited. Monthly rent starts at ₹82.45 lakh, equivalent to ₹21.06 per sq ft. Eicher has paid a security deposit of ₹5.24 crore. Rent payments will commence from May 2027 (or April 2027 as per some records), giving the company time to fit out the facility before commercial operations begin. The lease itself starts on August 31, 2026. After the first two years, rent and maintenance will escalate by 3.5% annually.

The facility is expected to serve as an auto spare parts consolidation centre for Royal Enfield. Industry observers note that the long-term commitment highlights robust demand for Grade-A industrial and logistics assets, driven by the growth of India's automotive and manufacturing sectors. Sriperumbudur remains a preferred location due to its established ecosystem of suppliers, connectivity and infrastructure.

Casagrand's industrial platform in the region has attracted institutional interest, including backing from global private equity major Blackstone, which has committed substantial capital to develop large-scale logistics and industrial parks nearby. Experts point out that prime hubs like Sriperumbudur continue to command strong tenant interest and capital allocation.

The move aligns with Eicher Motors' broader manufacturing strategy. While the company is also investing in a greenfield facility in Andhra Pradesh to expand Royal Enfield's production capacity, the Sriperumbudur lease reinforces its presence in Tamil Nadu, where it already has significant operations. For investors, the transaction signals continued confidence in the premium motorcycle segment and the need for efficient supply-chain infrastructure as volumes grow.

Overall, the deal reflects the healthy absorption of quality industrial space in South India and Eicher's pragmatic approach to supporting its expanding operations through strategic real-estate commitments.

जूनिपर ग्रीन एनर्जी का शानदार डेब्यू: आईपीओ प्राइस पर 9% प्रीमियम के साथ लिस्टिंग!

एनएसई पर 245 रुपये पर खुला शेयर, कर्ज घटाने की योजना और मजबूत संस्थागत मांग से बढ़ी निवेशकों की उम्मीद

मुंबई: जूनिपर ग्रीन एनर्जी के शेयरों ने गुरुवार को बाजार में मजबूत डेब्यू किया। कंपनी का शेयर आईपीओ प्राइस 225 रुपये के मुकाबले 9 प्रतिशत प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर यह 245 रुपये पर खुला, जबकि बीएसई पर 242 रुपये पर लिस्टिंग हुई।

इस लिस्टिंग से आवंटन पाने वाले निवेशकों को मामूली मुनाफा हुआ और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में स्थिर विश्वास का संकेत मिला। बीएसई के ओपनिंग प्राइस के आधार पर कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन करीब 13,770 करोड़ रुपये रहा। ग्रे मार्केट की उम्मीदों के अनुरूप यह मध्यम प्रीमियम रहा।

कंपनी का 1,800 करोड़ रुपये का आईपीओ पूरी तरह फ्रेश इश्यू था, जिसमें 8 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किए गए। प्राइस बैंड 214-225 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। इश्यू कुल 7.97 गुना सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबी ने 24.94 गुना, एनआईआई ने 1.82 गुना और रिटेल निवेशकों ने 93 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन दिया। एंकर निवेशकों से पहले ही 539.4 करोड़ रुपये जुटाए गए थे।

आईपीओ से जुटाई गई रकम का बड़ा हिस्सा बैलेंस शीट मजबूत करने में लगेगा। कंपनी अपने उधार की अदायगी के लिए 683.24 करोड़ रुपये और सहायक कंपनियों में कर्ज घटाने के लिए 728.69 करोड़ रुपये लगाएगी। कुल मिलाकर करीब 1,412 करोड़ रुपये कर्ज घटाने के लिए निर्धारित हैं, जिससे ब्याज लागत कम होगी और वित्तीय लचीलापन बढ़ेगा।

2011 में स्थापित जूनिपर ग्रीन एनर्जी भारत के अग्रणी रिन्यूएबल एनर्जी आईपीपी में से एक है। 30 जून 2026 तक इसका पोर्टफोलियो 7,910.20 मेगावाट का था, जो सोलर, विंड, हाइब्रिड और एफडीआरई सेगमेंट में फैला है। एफवाई26 में कुल आय 41 प्रतिशत बढ़कर 804.93 करोड़ रुपये और नेट प्रॉफिट 11 प्रतिशत बढ़कर 40.46 करोड़ रुपये रहा।

दीर्घकालिक पीपीए से राजस्व की दृश्यता मजबूत है। कर्ज में कमी और क्षमता विस्तार से भविष्य में रिटर्न रेशियो सुधरने की उम्मीद है। निवेशकों के लिए यह संतुलित वैल्यूएशन वाला डेब्यू है, जहां लंबी अवधि का प्रदर्शन प्रोजेक्ट एक्जिक्यूशन और नीतिगत माहौल पर निर्भर करेगा।

Juniper Green Energy

L&T Secures Ultra-Mega Order Worth Over ₹15,000 Crore from ADNOC Offshore

Major EPCIC Contract Strengthens Presence in Middle East Energy Sector

Mumbai: Larsen & Toubro's Energy Hydrocarbon Offshore business (LTEH Offshore) has secured an ultra-mega order valued at more than ₹15,000 crore from ADNOC Offshore for the development of multiple offshore facilities in the Middle East.

Under L&T's project classification, orders exceeding ₹15,000 crore are categorised as ultra-mega. The project will be executed through a consortium arrangement, with LTEH Offshore serving as the lead partner. The company will handle the major share of the scope, covering engineering, procurement, construction, installation and commissioning (EPCIC) of new offshore facilities as well as upgrades to existing infrastructure.

A significant portion of the fabrication work will be carried out at L&T's fabrication yards, leveraging its integrated capabilities and proven track record in delivering complex offshore projects in the region.

Commenting on the win, L&T Chairman and Managing Director S.N. Subrahmanyan said the award reflects the trust clients place in the company's engineering excellence and project execution capabilities. He reaffirmed L&T's commitment to supporting the UAE's energy ambitions through innovative and sustainable offshore solutions.

The contract further strengthens L&T's order book and reinforces its position as a key player in the global offshore oil and gas infrastructure segment, particularly in the strategically important Middle East market.

सिपला और रॉकेट इंडिया का कर्नाटक में ₹300 करोड़ का विस्तार

ब्लैकस्टोन डेटा सेंटर और रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश की संभावना तलाश रहा

नई दिल्ली: दवा निर्माता सिपला और प्लांट-बेस्ड प्रोटीन निर्माता रॉकेट इंडिया ने कर्नाटक में कुल ₹300 करोड़ के विस्तार की घोषणा की है। साथ ही, वैश्विक निवेशक ब्लैकस्टोन ने राज्य में डेटा सेंटर, नवीकरणीय ऊर्जा और फाइबर-ऑप्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की संभावनाएं तलाशने का संकेत दिया है।

ये घोषणाएं कर्नाटक सरकार के मुंबई में आयोजित दो दिवसीय निवेश रोडशो के दौरान हुईं। बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एम.बी. पाटिल के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य ने नए निवेश आकर्षित करने पर जोर दिया।

सिपला बेंगलुरु के बोम्मासंद्रा स्थित अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ₹200 करोड़ का निवेश कर क्षमता विस्तार करेगी। विस्तारित सुविधा से उत्पादन दिसंबर तक शुरू होने की उम्मीद है। रॉकेट इंडिया बेलागवी जिले के गोकक स्थित अपनी इकाई में ₹100 करोड़ का निवेश करेगी। कंपनी प्लांट-बेस्ड प्रोटीन उत्पाद बनाती है और उसे कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

ब्लैकस्टोन के साथ हुई चर्चा में डेटा सेंटर, रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहा। राज्य सरकार ने सेंट-गोबेन, हेन्केल, केईसी इंटरनेशनल और आइडियाफोर्ज जैसी कंपनियों से भी बातचीत की। ये निवेश कर्नाटक को फार्मा, फूड प्रोसेसिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य विनिर्माण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।

Climatetech Startup Mitti Labs Raises $9.5 Million in Series A

Aramco Ventures Leads Round to Scale Water-Resilient Rice Farming Across Asia

Bengaluru: Climate-tech startup Mitti Labs has raised $9.5 million in a Series A funding round led by Aramco Ventures, the venture arm of Saudi Aramco. Existing and new investors including Lightspeed India, Godrej Industries Group, Cisco Foundation, Francis Family Fund and Volta Circle also participated.

With this round, Mitti Labs has raised a total of $12.5 million since its launch. The company uses satellite imagery, artificial intelligence and on-ground operations to help rice farmers reduce water consumption and methane emissions. Its Geo AI platform creates digital twins of individual rice fields, enabling practices such as Alternate Wetting and Drying that can cut water use by around 40 per cent and methane emissions by over 50 per cent without affecting yields.

Mitti Labs currently works with more than 100,000 farmers across several Indian states, up from about 8,000 in its first season. The fresh capital will be used to expand operations in India and launch projects in the Philippines later this year, followed by Indonesia and other Southeast Asian markets in 2027.

The investment marks Aramco Ventures' first bet on an Indian startup. The funding will support the company's goal of reaching millions of smallholder farmers by 2030 and strengthening climate resilience in Asia's water-intensive rice farming systems.

रिवर मोबिलिटी ने जुटाए 120 मिलियन डॉलर, प्रीमियम ईवी स्कूटर सेगमेंट में मजबूत दावा

सीरीज सी फंडिंग से उत्पादन क्षमता बढ़ाने और नए मॉडल लॉन्च की तैयारी

बेंगलुरु: इलेक्ट्रिक स्कूटर स्टार्टअप रिवर मोबिलिटी ने 120 मिलियन डॉलर (लगभग ₹1,000 करोड़) की सीरीज सी फंडिंग जुटाई है। यह राउंड एलेवन वेंचर पार्टनर्स और क्लेपॉन्ड कैपिटल के नेतृत्व में हुआ, जिसमें सिंगुलैरिटी एएमसी, एनिकट कैपिटल, 360 वन एसेट, जेआईएफ कैपिटल और एचडीएफसी एएमसी सहित मौजूदा निवेशक यामाहा मोटर, अल-फुत्तैम ग्रुप और मित्सुई ने भी भाग लिया।

इस फंडिंग के साथ कंपनी का कुल पूंजी जुटाना 144 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। रिवर मोबिलिटी मुख्य रूप से अपने इंडि मॉडल पर फोकस कर रही है, जिसकी मासिक बिक्री करीब 6,000 यूनिट है। कंपनी ने अब तक 50,000 से अधिक यूनिट बेची हैं और 75 से अधिक स्टोर्स के माध्यम से काम कर रही है।

नए फंड का इस्तेमाल उत्पादन क्षमता बढ़ाने, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने, रिटेल नेटवर्क का विस्तार करने और नए मॉडल लॉन्च करने में किया जाएगा। कंपनी का लक्ष्य 2027 के मध्य तक नई फैक्ट्री शुरू करना और वार्षिक क्षमता 7-8 लाख यूनिट तक पहुंचाना है। वित्त वर्ष 2026 में कंपनी की राजस्व वृद्धि 330 प्रतिशत रही।

रिवर मोबिलिटी प्रीमियम और क्वालिटी-केंद्रित रणनीति के साथ ईवी दोपहिया बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। यह फंडिंग भारतीय इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में बड़े निवेश का संकेत है और कंपनी की विस्तार योजनाओं को गति देगी।

Skyroot Seeks $2 Billion Valuation in New Funding Round After Vikram-1 Success

Company Flips Script by Inviting Investor Bids; Aims to Raise Around $200 Million

Hyderabad: Space-tech startup Skyroot Aerospace has flipped the traditional fundraising script by asking investors to submit bids for a new funding round at a valuation of around $2 billion, capitalising on the successful launch of its Vikram-1 rocket.

The company is expected to raise approximately $200 million in the round. Investment bank Kotak is managing the process. Existing backers such as Singapore's GIC and Temasek are understood to be evaluating further investments, while domestic investor 360 One is also among those in discussions.

This marks a sharp rise from Skyroot's previous funding round in May 2026, when it raised $60 million at a $1.1 billion valuation and became India's first space-tech unicorn. The successful orbital launch of Vikram-1 on July 18 has significantly strengthened investor confidence in the Hyderabad-based firm.

Skyroot, founded by Pawan Kumar Chandana and Naga Bharath Daka, has positioned itself as a leader in India's private space sector. The fresh capital is expected to support higher launch cadence, manufacturing scale-up and development of the heavier Vikram-2 rocket.

The move reflects growing global interest in India's private space ecosystem and Skyroot's rising stature following its landmark launch achievement. Deal terms may evolve as discussions progress.

WEEKLY STOCK PIVOT LEVEL

Anil Bhardwaj
Technical Head
anil.stockcare@gmail.com

All level indicated above are based on future prices PP: Pivot Point: This is TRIGGER POINT for buy/sell Based on the price range of the previous Month, R1: Resistance one: 1st Resistance over PP; R2: resistance Two: 2nd Resistance over R1; S1: Support one: 1st support after PP; S2: Support Two: 2nd support after S1

• As per tool, trader should take Buy position just above pp and keep the stop loss of PP and 1st target would be R1
• If R1 is crossed then R2 becomes the next target with the stop loss at R1
• If R2 is crossed then R3 becomes the next target with the stop loss at R2.
• Similarly, if price goes below PP the trader should SELL price below PP as stop loss and the first target would be S1,
• If S1 is crossed then S2 becomes the next target with the stop loss at S1,
• If S2 is crossed then S3 becomes the next target with the stop loss at S2.

Stock Name	closing	R3	R2	R1	PP	S1	S2	S3
NIFTY	24571	25100	24937	24754	24591	24408	24245	24062
BANK NIFTY	57746	59107	58677	58212	57782	57317	56887	56422
SENSEX	78955	80259	79701	79328	78770	78397	77839	77466
FINNIFTY	26466	27347	27165	26816	26634	26285	26103	25754
MIDCAP	14875	15120	15037	14956	14873	14792	14709	14628
ACC	1367	1455	1434	1401	1380	1347	1326	1293
AXISBANK	1242	1308	1290	1266	1248	1224	1206	1182
ABCAPITAL	408	452	441	425	414	398	387	371
BHARTIARTL	1956	2108	2069	2013	1974	1918	1879	1823
BHEL	403	431	425	414	408	397	391	380
BIOCON	427	462	452	440	430	418	408	396
BEL	402	426	415	408	397	390	379	372
CDSL	1330	1407	1385	1357	1335	1307	1285	1257
DATAPATTERN	4379	4980	4802	4591	4413	4202	4024	3813
ESCORTS	3060	3271	3222	3141	3092	3011	2962	2881
EICHERMOTOR	8000	8306	8185	8093	7972	7880	7759	7667
FEDERAL BANK	358	391	381	370	360	349	339	328
GRINFRAPOJECT	868	1008	977	922	891	836	805	750
HDFCBANK	732	779	768	750	739	721	710	692
HCLTECH	1349	1422	1400	1374	1352	1326	1304	1278
HINDUNILVR	2096	2201	2169	2133	2101	2065	2033	1997
HAL	4908	5418	5194	5051	4827	4684	4460	4317
HYUNDAI	2197	2302	2275	2236	2209	2170	2143	2104
IOC	143	148	146	145	143	142	140	139
ICICIBANK	1425	1491	1476	1450	1435	1409	1394	1368
INFY	1175	1243	1214	1195	1166	1147	1118	1099
ITC	285	301	297	291	287	281	277	271
KOTAKBNK	389	409	404	397	392	385	380	373
LICHOUSING	504	544	535	520	511	496	487	472
LT	4040	4199	4137	4088	4026	3977	3915	3866
LUPIN	2371	2517	2478	2425	2386	2333	2294	2241
MARUTI	14015	14995	14718	14366	14089	13737	13460	13108
M&M	3502	3661	3583	3542	3464	3423	3345	3304
MGL	1144	1192	1168	1156	1132	1120	1096	1084
MAZGAONDOC	2525	2816	2695	2610	2489	2404	2283	2198
PFC	419	444	436	428	420	412	404	396
RECLTD	366	391	384	375	368	359	352	343
RELIANCE	1329	1421	1379	1354	1312	1287	1245	1220
SBIN	1097	1230	1177	1137	1084	1044	991	951
SUNPHARMA	1946	2044	2016	1981	1953	1918	1890	1855
SHRIRAMFINANCE	1115	1264	1209	1162	1107	1060	1005	958
TITAN	4944	5168	5087	5015	4934	4862	4781	4709
TCS	2455	2603	2538	2497	2432	2391	2326	2285
TATAMOTORS	346	362	357	352	347	342	337	332
UPL	572	660	641	607	588	554	535	501
VALIENT	293	331	313	303	285	275	257	247
WIPRO	187	196	193	190	187	184	181	178

Gen Z Holds the Key to India's ₹315 Lakh Crore Gold Opportunity

World Gold Council Report Says Digital-Savvy Youth Can Unlock Idle Household Holdings

New Delhi: Gen Z could help unlock the economic potential of India's vast household gold reserves, estimated at over 31,000 tonnes and valued at nearly ₹315 lakh crore ($3.4 trillion), according to the World Gold Council's 'Swarnim Udaan 2047' report.

Unlike previous generations that largely viewed gold as jewellery or a family heirloom, Gen Z, those born between 1997 and 2012 increasingly sees it as a flexible financial asset. This shift is driving demand for digital gold, gold ETFs, sovereign gold bonds and other technology-enabled investment products.

The report highlights that mobilising even a small portion of these idle holdings could deepen financial markets, improve liquidity, strengthen capital formation and reduce dependence on imported bullion. Gen Z is expected to drive nearly $2 trillion in consumer spending by 2035, positioning them as a powerful force in reshaping India's gold ecosystem.

To capitalise on this opportunity, the World Gold Council recommends building an integrated framework that connects the gold monetisation scheme, recycling networks, electronic gold receipts, digital gold platforms, bullion banking and gold-backed financial products.

Experts believe that modernising the gold market through digital channels and greater financialization will allow India to transform locked household wealth into a productive economic resource, supporting long-term growth and the vision of a more resilient financial system.

Disclaimer: This content is for educational purposes only. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.

प्रकाशक एवं मुद्रक: प्रदीप कारबेलकर, सी-101, नेहरू नगर स्वत्वाधिकार द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज प्रा.लि., इ-4, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश 462016, से प्रकाशित एवं DigitalLok, सागर हाई स्ट्रीट, अयोध्या बायपास रोड, डी मार्ट के पास, भोपाल, (म.प्र.) - 462010। संपादक: प्रदीप कारबेलकर (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)। फोन: +9198262 23075 वेबसाइट: www.investmentavenues.in